

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक ०९ मार्च, 2017

विषय— कुटुम्ब न्यायालय, जिला पौड़ी गढ़वाल, जिला नैनीताल, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून, कुटुम्ब न्यायालय, जिला हरिद्वार तथा जिला उधमसिंह नगर, कुटुम्ब न्यायालय, रुड़की (जिला हरिद्वार) तथा ऋषिकेश (जिला देहरादून), अपर कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून, कुटुम्ब न्यायालय जिला अल्मोड़ा एवं जिला टिहरी गढ़वाल, कुटुम्ब न्यायालय काशीपुर (जिला उधमसिंह नगर), कुटुम्ब न्यायालय, हल्द्वानी (जिला नैनीताल), विकासनगर (जिला देहरादून), जिला मुख्यालय देहरादून एवं जिला मुख्यालय उधमसिंह नगर, कुटुम्ब न्यायालय, कोटद्वार (जिला पौड़ी गढ़वाल), खटीमा (जिला उधमसिंह नगर) के लिये सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुटुम्ब न्यायालय, जिला पौड़ी गढ़वाल, जिला नैनीताल, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून, कुटुम्ब न्यायालय, जिला हरिद्वार तथा जिला उधमसिंह नगर, कुटुम्ब न्यायालय, रुड़की (जिला हरिद्वार) तथा ऋषिकेश (जिला देहरादून), अपर कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून, कुटुम्ब न्यायालय जिला अल्मोड़ा एवं जिला टिहरी गढ़वाल, कुटुम्ब न्यायालय काशीपुर (जिला उधमसिंह नगर), कुटुम्ब न्यायालय हल्द्वानी (जिला नैनीताल), विकासनगर (जिला देहरादून), जिला मुख्यालय देहरादून एवं जिला मुख्यालय उधमसिंह नगर, कुटुम्ब न्यायालय, कोटद्वार (जिला पौड़ी गढ़वाल), खटीमा (जिला उधमसिंह नगर) के लिये सृजित अस्थायी पदों की वर्ष 2017-18 में दिनांक 01-03-2017 से 28-2-2018 तक की निरन्तरता बढ़ाये जाने की, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दी जाये, वर्तमान लाभ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त न्यायालय/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या-3034/सात-न्याय अनुभाग-2-226/89, दिनांक 15-11-1995, शासनादेश संख्या-321/न्याय अनुभाग/2001 दिनांक 24-12-2001, शासनादेश संख्या-38-एक(1)/न्याय विभाग/2004, दिनांक 15-4-2004, शासनादेश संख्या-170/xxxvi(3)/2013-08/01-T.C., दिनांक 27-06-2013, शासनादेश संख्या-83/xxxvi(3)/2016-155/2015, दिनांक 02-08-2016, शासनादेश संख्या-128/xxxvi(3)/2016-208/ 2001-T.C.-II, दिनांक 06-09-2016, शासनादेश संख्या-155/xxxvi(3)/2016-208/2001-T.C., दिनांक 27-09-2016, शासनादेश संख्या-165/xxxvi(3)/2016-154(सा0)/2015, दिनांक 13-10-2016, शासनादेश संख्या-94/xxxvi(3)/2016-208/2001-T.C.-II, दिनांक 25-10-2016 द्वारा किया गया है।

- 2- उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी।
- 3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-04-पारिवारिक न्यायालय-00 के नामें डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 7-11-92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( आलोक कुमार वर्मा )  
सचिव।

संख्या- 37/(1)/xxxvi(2)/2017-208/2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2- जिला न्यायाधीश, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल एवं उधमसिंहनगर।
- 3- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय देहरादून, कुटुम्ब न्यायालय, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल एवं उधमसिंह नगर।
- 4- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी एवं उधमसिंहनगर।
- 5- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( महेश चन्द्र कौशिवा )  
अपर सचिव।